Volume: 3 Issue: 1 Pages: 91-96

# देश की शैक्षिक प्रगति में प्रौढ़ शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की भूमिकाः एक अध्ययन

**[*1]डॉ. नवनीत कुमार सिंह**

[*1]विभागाध्यक्ष (बी.एड.), शिक्षा विभाग, चन्द्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, भारत।

**Article Info.**
**E-ISSN: 2583-6528**
**Impact Factor (SJIF): 5.231**
**Peer Reviewed Journal**
**Available online:**
**www.alladvancejournal.com**

**Received:** 26/Dec/2023
**Accepted:** 29/Jan/2024

***Corresponding Author**
**डॉ. नवनीत कुमार सिंह**
विभागाध्यक्ष (बी.एड.), शिक्षा विभाग, चन्द्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, भारत

**सारांश**
किसी भी देश के लिये निरक्षरता किसी अभिशाप से कम नहीं है। निरक्षर वह होता है जो पढ़ और लिख नहीं सकता है, अर्थात अक्षरों या शब्दों से अनभिज्ञ हो। निरक्षरता सिर्फ पढ़ने–लिखने में असमर्थता ही नहीं, बल्कि किसी विशेष ज्ञान या सूचना से परिचित न होने को भी दर्शा सकती है, जैसे ''सांकेतिक रूप से निरक्षर''। सरकार द्वारा देश की निरक्षरता को दूर करने के लिये राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा योजना व राष्ट्रीय साक्षरता अभियान का एक विशाल कार्यक्रम तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर वयस्कों को शिक्षित करना है। कोठारी आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में कहा था कि, "जो देश आर्थिक उन्नति, सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा चाहता है, उसे अपने वयस्क नागरिकों को विकास कार्यक्रमों में कुशलता एवं बुद्धिमत्ता से भाग लेने की शिक्षा देनी चाहिए। यह बात भारत के लिए विशेष रूप से सत्य है, क्योंकि यहाँ के विशाल जनसमूहों को विद्यालयों में किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है और जिनको शिक्षा प्राप्त भी हुई है, वह विकास–कार्यक्रमों के लिए व्यर्थ है। जो कृषक, भूमि को जोतता है, उसे भूमि की बनावट का ज्ञान होना चाहिए। जो श्रमिक, मशीन को चलाता है, उसे मशीन के अंगों का ज्ञान होना चाहिए। कृषकों, श्रमिकों आदि को अपने कार्यों का ज्ञान नहीं है।" अतः उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जानी आवश्यक है।
2020 में केन्द्र सरकार ने पूरे देश में शिक्षा में सुधार की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021–22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 2022–2027 की अवधि के लिए ''नव भारत साक्षरता कार्यक्रम'' को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम को लागू करने का उद्देश्य भारत के जन–जन को 2030 तक शत प्रतिशत साक्षर बनाना है।

**मुख्य शब्दः** शैक्षिक प्रगति, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान।

## प्रस्तावना
*''सब ते भले विमूढ़, जिन्हें न व्यापै जगत गति''* मूर्खों के लिए गोस्वामी जी का यह व्यंग इसलिए सार्थक है कि जहाँ समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए संसार में पग–पग पर ठोकरें हैं, चिन्तायें हैं, उलझनें हैं, वहाँ मूर्ख आराम से निश्चित होकर अपनी जिन्दगी काट लेता है, न उसे अपने कर्त्तव्य के विषय में सोचना पड़ता है, न उसे घर की इज्जत सताती है और न बाहर की चिन्ता, उसे समाज से न कोई मतलब रहता है और न देश से कोई सम्बन्ध। कोल्हू के बैल की तरह जिस रास्ते पर आप

उसे डाल देंगे उसी को वह अपने जीवन का लक्ष्य समझकर चलता चला जायेगा। अब प्रश्न यह है कि वह कौन–सी विशेषता है? जो पशुता से मनुष्यता में विभक्त कर सकती है। उत्तर में यही कहा जायेगा कि वह विशेषता है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा द्वारा ही मनुष्य, पशु से इन्सान बनता है। यदि आप कलाकार और गुणी हैं, तो सरकस का कुत्ता और हाथी भी बड़ी–बड़ी करामतें दिखा देता है। शिक्षा ऐसी विशेषता है जिसे अगर जानवरों को भी दी जायें तो वह भी उससे ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अतः यदि आप अशिक्षित या निरक्षर हैं, तो पशु ही हैं। अशिक्षित व्यक्ति न अपने घर का वातावरण शिष्ट बना सकता है और न अपने बच्चों के भविष्य का ही निर्माण कर सकता है। इस प्रकार निरक्षरता के कारण न तो देश के भावी नागरिक ही अच्छे बन पाते हैं और न मनुष्य आत्म–कल्याण और राष्ट्र–कल्याण की ओर ही उन्मुख हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश की निरक्षरता के कारण देशवासियों को सभी प्रकार के घोर कष्टों का सामना करना पड़ता है। [1]

**साक्षरता आन्दोलनः** देश की निरक्षरता को दूर करने के लिये राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा योजना व राष्ट्रीय साक्षरता अभियान का एक विशाल कार्यक्रम तैयार किया गया है और इन्हें लागू करने के व्यापक प्रबन्ध किये गये। राष्ट्रीय आन्दोलन के फलस्वरूप सन् 1937 ई0 में जब प्रान्तों में लोकप्रिय सरकारों की स्थापना हुई तो देश के असंख्य अनपढ़ नर–नारियों को साक्षर बनाने के प्रयत्न प्रारम्भ हुये। गाँव–गाँव में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र तथा रात्रि पाठशालायें खोली गई, पुस्तकालय तथा वाचनालय स्थापित किये गये। [2]

**प्रौढ़ शिक्षा अभियानः** भारत में प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (NAEP) के साथ 2 अक्टुबर 1978 हो हुई, जिसका उद्देश्य 15 से 35 वर्ष की आयु के निरक्षर वयस्कों को शिक्षित करना था। इस कार्यक्रम ने देश में निरक्षरता को खत्म करने और साक्षरता दर को बढ़ाने पर जोर दिया। प्रौढ़ शिक्षा को भिन्न–भिन्न नामों से सम्बोधित किया जाता है। साक्षरता, समाज शिक्षा, जीवन पर्यन्त शिक्षा, उद्देश्यपूर्ण शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, द्वितीय अवसर की शिक्षा, या प्रौढ़ शिक्षा जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है इन सभी नामों में प्रौढ़ शिक्षा नाम सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। भारत सरकार ने भी प्रौढ़ शिक्षा नाम ही अपनाया है। अतः आगे इसी नाम का प्रयोग ही किया जायेगा। लेकिन देश के शिक्षा मंत्रालय द्वारा अब प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदलकर 'सभी के लिए शिक्षा' रखा गया है। एक प्रगतिशील कदम के रूप में, यह भी निर्णय लिया गया है कि अब से ''प्रौढ़ शिक्षा'' के स्थान पर ''सभी के लिए शिक्षा'' शब्द का प्रयोग किया जाएगा।

प्रौढ़ शिक्षा से हमारा आशय यह है कि ऐसे निरक्षर व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जाये, जो विषम परिस्थितियों में रहकर शिक्षा प्राप्त करने में असफल रहे और परम्परागत व्यवसाय में लग गये हैं। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से ऐसे निरक्षर व्यक्तियों को न केवल साक्षर बनाना है वरन् उन्हें तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान देकर नागरिकता के अधिकारों और कर्त्तव्यों से भी अवगत कराना है। भारत जैसे प्रजातान्त्रिक व विकासशील देश में प्रौढ़ शिक्षा की नितान्त आवश्यकता है। [3] भारतीय प्रजातन्त्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय जनता शिक्षित हो, यदि भारतवर्ष राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में उन्नति करना चाहता है तो देश की सरकार एवं शिक्षित नव–युवकों को चाहिए कि वे हमारे भारतीय समाज में पैर तोड़कर बैठी हुई निरक्षरता जैसी पिषाचिनी को भगा दें। इसको भगा देने का सर्वप्रथम एवं सुविधापूर्ण माध्यम देश में प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार और प्रचार है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बुडरो विल्सन ने कहा था कि, ''प्रजातन्त्र शासन की सफलता के लिए आवश्यक है कि अपनी सामान्य जनता को शिक्षित करें।'' [4] श्री अब्बुल कलाम के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ केवल साक्षर बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करने हैं जो आधुनिक प्रजातांत्रिक तथा सामाजिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने प्रौढ़ शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा था कि, ''यह जीवन के लिए जीवन के द्वारा जीवन भर की शिक्षा है।'' [5]

प्रौढ़ शिक्षा की परिकल्पना भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वथा नवीन नहीं है। देश की स्वाधीनता से पूर्व भी अनेक समाज सेवी भारतीयों ने इस दिशा में कुछ प्रयास किये थे। परन्तु आज प्रौढ़ शिक्षा का प्रश्न और भी ज्वलन्त हो गया है। गाँधी जी भी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को बड़ा महत्व देते थे और डॉ0 राममनोहर लोहिया भी प्रौढ़ शिक्षा के हामी थे। [6]

अतएव सन् 1949 ई0 में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने राज्य मन्त्रियों के सम्मेलन में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की एक योजना प्रस्तुत की। सन् 1950 ई0 में 'शैक्षणिक कारवाँ' योजना के अधीन देश के गाँव–गाँव में प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया गया। सन् 1951 ई0 में अलीपुर नामक गाँव में प्रथम जनता कॉलेज स्थापित किया गया। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय दिल्ली की पब्लिक लाइब्रेरी ने प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयत्न किये। 5 दिसम्बर, 1969 ई0 को एक प्रौढ़ साक्षरता मण्डल की स्थापना की गई, जिसने प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को आगे बढ़ावा दिया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के प्रथम प्रधानमन्त्री के रूप में पं0 जवाहरलाल नेहरू ने प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को पंचवर्षीय योजनाओं में भी प्रमुख स्थान दिया। [7]

पिछले कुछ वर्षों में प्रौढ़ शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा को जन–जन तक पहुँचाने पर बल दिये जाने के बावजूद निरक्षरों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि साक्षरता के प्रतिशत में सुधार हुआ है परन्तु निरक्षरों की संख्या विगत 30 वर्षों में 1.5 गुनी से अधिक हो गई है। सन् 1951 ई0 में देश में 30 करोड़ व्यक्ति निरक्षर थे जो सन् 1981 ई0 में बढ़कर 44 करोड़ हो गये हैं। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय साक्षरता

मिशन की रचना की गई।

**राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (The National Literacy Mission):**

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुभारम्भ 5 मई 1988 ई0 को प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाँधी के द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था। इसी दिन इस मिशन का प्रारम्भ राज्य स्तर पर राज्यों की राजधानियों में भी किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 15 वर्षों से 35 आयु वर्ग के 3 करोड़ निरक्षरों को सन् 1990 तक तथा अन्य 5 करोड़ को सन् 1995 ई0 तक साक्षर बनाना है। इस प्रकार से सन् 1995 ई0 तक कुल 8 करोड़ निरक्षरों को साक्षर करने का संकल्प था। साक्षरता मिशन के अर्न्तगत पढ़ना, लिखना और अंकगणितीय कौशल (3R) शामिल थे। इसका लक्ष्य सामाजिक मुद्दों और राष्ट्रीय विकास में भाग लेने के लिए व्यक्तियों को सशक्त बनाना था। मुख्य बल ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर महिलाओं तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के निरक्षरों पर दिया गया। [8] साक्षरता के प्रचार व प्रसार को राष्ट्र के पाँच तकनीकी मिशनों में से एक माना गया जिससे तकनीकी व विज्ञान की खोज का लाभ समाज के उपेक्षित वर्गों को भी मिल सके। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एक सामाजिक मिशन है। इसका अर्थ है कि मिशन के लक्ष्यों को पाने के लिए सभी जगहों पर राजनैतिक संकल्प मौजूद है, सामाजिक शक्तियों को जुटाया जा सकता है, तथा लोगों की छिपी शक्तियों को जगाकर उनसे साक्षरता अभियान में सहयोग लिया जा सकता है। [9]

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत भारत में साक्षरता की दर 1991 में 52.21 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001 में 64.84 प्रतिशत हो गई। इस अवधि के दौरान अशिक्षितों की संख्या 328.88 मिलियन से कम होकर 304 मिलियन हो गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में गैर–साक्ष्यों की कुल संख्या 25.76 करोड़ (पुरुष 9.08 करोड़, महिला 16.68 करोड़) है। 2009–10 से 2017–18 के दौरान साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत साक्षर के रूप में प्रमाणित व्यक्तियों की 7.64 करोड़ की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान में भारत में लगभग 18.12 करोड़ वयस्क अभी भी गैर–साक्षर हैं। [10]

2014 में केन्द्र सरकार में परिवर्तन के उपरान्त देश के समस्त क्षेत्रों बहुत तेजी से विकास प्रारम्भ हुआ, इसी विकास क्रम में देश में साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने के लिये बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा के नये संस्थान स्थापित किये गये हैं जिसमें 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 3000 नये आईटीआई, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय शामिल हैं। केन्द्र सरकार ने पूरे देश में शिक्षा में सुधार की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021–22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 2022–2027 की अवधि के लिए ''न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम (नव भारत साक्षरता कार्यक्रम)'' को मंजूरी दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन सीखने की सिफारिशें शामिल हैं। प्रौढ़ शिक्षा अभियान, जिसे अब 'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' के रूप में जाना जाता है, यह 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षर वयस्कों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्रदान करने का एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल और बुनियादी शिक्षा प्रदान करना भी है। यह कार्यक्रम 2022 से 2027 तक लागू किया जाएगा और इसका लक्ष्य हर साल 1 करोड़ शिक्षार्थियों को शामिल करना है। [11]

**निरक्षरता पर विभिन्न समाजवादी चिन्तकों के विचार:**

सभी समाजवादी चिन्तक देश में व्याप्त निरक्षरता को कंलक मानते थे। उनके अनुसार लोगों में शिक्षा के प्रति अरूचि तथा पर्याप्त शैक्षिक सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण निरक्षरों की संख्या बढ़ती जा रही है। अतः समस्त समाजवादियों ने माना कि "शिक्षा साक्षरता से बड़ी चीज हैं।" उन्होंने समाज सेवा को पाठ्यक्रम का अंग बनाने की संस्तुति की। पंडित नेहरू निरक्षरता को अभिशाप मानते थे। देश के प्रधानमंत्री होने के बाद उन्होंने निरक्षरता को दूर करने के लिए सरकारी नीतियों का निर्धारण किया तथा साक्षरता अभियान को पूरे देश में लागू करने का आदेश जारी किया था। उन्होंने भी गाँधी जी की तरह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का आह्वान किया था। गाँधी जी ने कहा था कि "साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न प्रारम्भ यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा नर और नारी को शिक्षित किया जा सकता है।" भारत के महान् शिक्षाविद्ों में आचार्य नरेन्द्रदेव व डॉ0 सम्पूर्णानन्द का विशिष्ट स्थान रहा है। दोनों ने अनुभव किया कि देश में राजनैतिक सुदृढ़ता, सामाजिक, आर्थिक व नैतिक प्रगति का आधार शिक्षा ही है। शिक्षा मात्र साक्षरता नहीं है। साक्षरता शिक्षा का साध्य नहीं, वरन् एक साधन मात्र है। शिक्षा का अभिप्राय बालक व बालिकाओं के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाये जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास है। दोनों ही साक्षरता के अभियान को सामाजिक शिक्षा का रूप देना चाहते थे। व्यापक जन शिक्षा की पूर्ति के लिये श्रमिकों, किसानों तथा दूसरे उत्पादों के लिये उनके घरों तथा कार्यस्थलों के निकट प्रौढ़ शैक्षिक संस्थायें खोली जायें और इन संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा के साथ–साथ सांस्कृतिक कार्यों की भी व्यवस्था हो। जयप्रकाश नारायण व डॉ0 लोहिया के अनुसार साक्षरता व्यापक जन शिक्षा का प्रथम कदम है। इससे बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं। दोनों ने पूरे देश को साक्षर बनाने के लिए कहा कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में सभी देशवासियों को मिलकर साथ देना चाहिए तभी इस निरक्षरता रूपी कंलक को धोया जा सकता है। सभी के सहयोग बिना पूरे देश को साक्षर बनाना सम्भव नहीं है।

वर्तमान में, भारत सरकार द्वारा पूरे देश को साक्षर बनाने के लिए निम्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैः–

- **केन्द्रीय विद्यालय (Central School):** केन्द्रीय विद्यालय

में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है। इसकी शुरुआत 15 दिसम्बर, 1963 में हुई तथा यह तब से भारत के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबन्धित है। इस समय भारत में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या (1,257) है। जिसमें तीन विदेश में (मॉस्को, तेहरान और काठमांडू) हैं, जिनमें भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों तथा अन्य प्रवासी भारतीयों के बच्चे पढ़ते हैं। विद्यालयों में भारत के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम का अनुसरण होता है। सभी केन्द्रीय विद्यालयों का संचालन केन्द्रीय विद्यालय संगठन नाम की संस्था करती है। ये विद्यालय शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में संचालित होते है।

- **मुक्त विश्वविद्यालय (Open University):** मुक्त विश्वविद्यालय, जिन्हें खुला विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, वे संस्थान हैं जो दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय 1982 में स्थापित किया गया था। इसका नाम डॉ. बी.आर. अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय है, जो हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद, 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की स्थापना नई दिल्ली में हुई। ये विश्वविद्यालय पारंपरिक विश्वविद्यालयों के विपरीत, शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली तक पहुंचने में असमर्थ हैं। यह छात्रों को कक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता के बिना, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा को अधिक सुलभ और किफायती बनाते हैं, और छात्रों को अपनी गति और सुविधा के अनुसार अध्ययन करने की अनुमति देते हैं। ये छात्रों को विभिन्न माध्यमों से शिक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कि अध्ययन सामग्री, ऑनलाइन कक्षायें, और रेडियो या टेलीविजन कार्यक्रम। सभी को शिक्षा सुलभ कराने के उद्देश्य से देश के प्रत्येक राज्य में एक–एक मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। [12]
- **जवाहर नवोदय विद्यालय (Jawahar Navodaya Vidyalaya):** राजीव गाँधी के स्वप्न को साकार करती यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च गुणवत्ता की कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करती है। 1986 में, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रणाली की स्थापना की गयी, जो केंद्र सरकार–आधारित शिक्षा संस्थान है। यह केंद्रीय विद्यालयों की एक प्रणाली है और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) द्वारा संचालित हैं, जो शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। ये विद्यालय पूरी तरह से सह–शिक्षा और आवासीय हैं, वर्तमान में, भारत में कुल 661 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं।
- **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS):** एनआईओएस, जिसे पहले राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (NOS) के रूप में जाना जाता था। इसकी स्थापना 1989 में की गयी थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विद्यालयी शिक्षा संगठन है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में सभी के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना है. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है, जो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करता है। यह उन शिक्षार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प है जो पारंपरिक स्कूल प्रणाली में शिक्षा जारी रखने में सक्षम नहीं हैं। यह विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं: माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 10), उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 12), मुक्त व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (OVET), मुक्त बेसिक शिक्षा (OBI)। एनआईओएस शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। एनआईओएस के 23 क्षेत्रीय केंद्र और 7400 से अधिक अध्ययन केंद्र पूरे भारत में फैले हुए हैं।
- **मध्याह्न भोजन योजना** (Mid-day Meal Scheme)**:** यह योजना 15 अगस्त, 1995 को शुरू की गई थी। इसके अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का मुफ्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। यह योजना बच्चों में भूख, कुपोषण और स्कूल में कम उपस्थिति की समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। यह बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करती है और उनकी सीखने की क्षमताओं में सुधार करने में भी मदद करती है। 2021 में, योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया। [13]
- **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) (Eklavya Model Residential School):** यह विद्यालय भारत सरकार की एक आदर्श आवासीय विद्यालय योजना है, जो विशेष रूप से पूरे भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिये है। इसे वर्ष 1997–98 में आदिवासी छात्रों को दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पेश किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ईएमआरएस की स्थापना की जाती है। बजट 2018–19 के अनुसार, 50 से अधिक अनुसूचित जनजाति (ST) आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में वर्ष 2022 तक एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा। ये विद्यालय नवोदय विद्यालयों के समान हैं और सीबीएसई पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। इनका उद्देश्य आदिवासी बच्चों को उनकी अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के साथ–साथ मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना है। प्रत्येक स्कूल में 480 छात्रों

की क्षमता होती है, जिसमें लड़कों और लड़कियों के लिए समान सीटें होती हैं। इनमें डिजिटल शिक्षा के लिए स्मार्ट कक्षायें, कंप्यूटर लैब, आवास, भोजन और अन्य सुविधायें मुफ्त या कम लागत पर उपलब्ध हैं। सरकार स्कूल की स्थापना के लिए एकमुश्त 30 लाख का अनुदान देती है, अतिरिक्त लागत राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है। 2018 के अंत तक, कुल 284 ईएमआरएस स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से सबसे अधिक 32 मध्य प्रदेश में स्वीकृत हैं। देश भर में लगभग 226 ईएमआरएस कार्यरत हैं और उनमें से 68 सीबीएसई से संबद्ध हैं। भारत में 721 EMRS स्थापित करने की स्वीकृति है, जिनमें से 477 संचालित हैं। [14]

- **सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan):** सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा 2001 में शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। जिसका उद्देश्य 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए ''समयबद्ध तरीके से'' मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। यह कार्यक्रम भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के तहत मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा को मान्यता देने के बाद शुरू किया गया था। इसके लिए 2006–07 में 11,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसे वर्ष 2010 तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य था।
- **कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना (Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Scheme):** कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) योजना अगस्त, 2004 में शुरू की गई थी. इस योजना का उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 12 तक) पर आवासीय विद्यालय स्थापित करना था। इस योजना में शिक्षा के साथ–साथ बालिकाओं को छात्रावास में निवास करने की भी सुविधा है। इसके साथ ही 4 समय का भोजन, पहनने के लिए स्कूल यूनिफार्म, पाठ्यपुस्तकें और कॉपी–किताबें भी दी जाती है। वर्तमान में पूरे देश में 5,726 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्वीकृत हैं, जिनमें से 4,887 विद्यालय संचालित हैं. ये विद्यालय ''समग्र शिक्षा'' योजना के तहत चलाए जा रहे हैं।
- **पीएम श्री स्कूल योजना (PM Shri School Scheme):** ''पीएम श्री स्कूल योजना'' 7 सितंबर, 2022 को शुरू की गई थी। पीएम श्री (PM SHRI) का मतलब है ''प्रधान मंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया'' (Pradhan Mantri Schools for Rising India)। यह भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित एक योजना है और इसका कार्यान्वयन केंद्र सरकार, राज्यध्केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, स्थानीय निकायों, केंद्रीय विद्यालय संगठन (KV), और नवोदय विद्यालय समिति (NV) द्वारा किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य उभरते भारत के लिए देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों को अपग्रेड/विकसित करना है, ताकि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकें। इन स्कूलों की व्यवस्था के अर्न्तगत जहाँ प्रत्येक छात्र स्वागत और देखभाल महसूस करे, जहाँ एक सुरक्षित और उत्साहजनक शिक्षण वातावरण हो, जहाँ सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध हों, और जहाँ सभी छात्रों के लिए अच्छा भौतिक बुनियादी ढाँचा और सीखने के लिए उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हों। इस योजना से 20 लाख से ज्यादा छात्रों के सीधे लाभान्वित होने की उम्मीद है। 834 केंद्रीय विद्यालयों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में चुना गया है। इस योजना को 2022–23 से 2026–27 तक, पाँच वर्षों की अवधि में लागू करने का प्रस्ताव है। [15]

उपरोक्त के अतिरिक्त सारक्षरता मिशन को बल देने के लिये भारत सरकार पूरे देश में राज्यों की मदद से राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय माध्यामिक विद्यालय, राजकीय इन्टर कॉलेज, राजकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का संचालन कर रही है, जिसके अर्न्तगत देश के नवयुवक निशुल्क या बहुत कम शुल्क पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सरकार द्वारा चलाये जा रहे माध्यामिक स्तर तक के विद्यालयों में तो प्रत्येक छात्र–छात्रा को निशुल्क किताबें, बैग, यूनिफॉर्म, जूते एवं पौष्टिक मध्यान भोजन दिया जा रहा है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक छात्र–छात्रा को छात्रवृत्ति भी दी जा रही है।

## निष्कर्ष

देश को साक्षर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिनमें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (NLM), नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (NILP), और सर्व शिक्षा अभियान (SSA) शामिल हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य देश में निरक्षरता को कम करना और सभी नागरिकों को बुनियादी शिक्षा और कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। यह कार्यक्रम न केवल साक्षरता प्रदान करता है, बल्कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में जागरूक भी करता है। प्रौढ़ शिक्षा अभियान, जिसे अब ''नव भारत साक्षरता कार्यक्रम'' कहा जाता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी गैर–साक्षर वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए चलाया जा रहा एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्रदान करना है, बल्कि 21वीं सदी के नागरिकों के लिए आवश्यक जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा भी प्रदान करना है। इस कार्यक्रम को जन–जन साक्षर बनाने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है और स्वयंसेवा आधारित मॉडल पर आधारित है। इसका कार्यान्वयन ऑनलाइन मोड में भी स्वयंसेवा के माध्यम से किया जाएगा। [16] यह अभियान भारत को 2030 तक शत प्रतिशत साक्षर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची


1. गौड़, डॉ0 आर0 एन0 राजहंस हिन्दी निबन्ध, (राजहंस प्रकाशन मन्दिर, मेरठ, 2004), पृ0 147–148
2. गौड़, डॉ0 आर0एन0 राजहंस हिन्दी निबन्ध, (राजहंस प्रकाशन मन्दिर, मेरठ, 2004), पृ0 149
3. गौड़, डॉ0 आर0एन0 राजहंस हिन्दी निबन्ध, (राजहंस प्रकाशन मन्दिर, मेरठ, 2004), पृ0 274–275
4. कुलश्रेष्ठ, रमेशचन्द्र आदर्श निबन्ध, (विनोद पुस्तक मन्दिर), पृ0 141
5. गुप्ता, प्रो0 एस0पी0 भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास, (शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2007), पृ0 316
6. गौड़, डॉ0 आर0एन0 राजहंस हिन्दी निबन्ध, (राजहंस प्रकाशन मन्दिर, मेरठ), पृ0 257
7. गौड़, डॉ0 आर0एन0 राजहंस हिन्दी निबन्ध, (राजहंस प्रकाशन मन्दिर, मेरठ), पृ0 257
8. गुप्ता, प्रो0 एस0पी0 भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास, (शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2007), पृ0 325
9. गुप्ता, प्रो0 एस0पी0 भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास, (शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2007), पृ0 325
10. स्त्रोतः पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार।
11. www.google.com
12. https://wikipedia.org
13. https://en.wikipedia.org
14. According to News18 Hindi
15. https://dsel.education.gov.in
16. www.google.com